

प्रभात खबर
लीगल काउंसिलिंग आज



**अधिवक्ता गौरी शंकर प्रसाद
देंगे कानूनी सलाह**

प्रभात खबर की ओर से 28 मार्च (शनिवार) को लीगल काउंसिलिंग का आयोजन किया गया है। झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता गौरी शंकर प्रसाद लोगों को कानूनी सलाह देंगे। उन्होंने रांची विधिविद्यालय से लॉ की डिग्री लेने के बाद वर्ष 2001 में वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया था। अधिवक्ता गौरी शंकर प्रसाद से दूरभाष संख्या-06516613208 पर दिन के 11 से 12 बजे तक लोग कानून सलाह ले सकते हैं। अधिवक्ता सैवधानिक, सिविल व क्रिमिनल मामलों के जानकार हैं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग उनसे सवाल कर सकते हैं।

तिथि : 28 मार्च (शनिवार) समय : दिन के 11 से 12 बजे तक
दूरभाष संख्या : 0651-6613208

विक्क बाइट्स

पीएम के साथ बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत

रांची. पश्चिम एशिया में उभरते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान देश की तैयारियों की समीक्षा की गयी। झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मुख्य सचिव अविनाश कुमार इस वचुअल बैठक में शामिल हुए। पीएम ने राज्यों से कहा कि आपूर्ति श्रृंखला का सुचारु संचालन सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पीएम ने राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने तथा प्रशासनिक सतर्कता बनाये रखने पर भी बल दिया, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न आये। बताया गया कि कई मुद्दों पर सीएम हेमंत ने भी अपनी बात रखी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जायेंगे असम

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को असम जायेंगे। वह रांची से दिन के 10.30 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी रवाना होंगे। बताया गया कि पीएम के साथ शाम 6.30 से रात 8.30 बजे तक बैठक चलने के कारण वह शुक्रवार को नहीं जा सके। शनिवार को दिन के 2.20 बजे असम के गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।

जय झारखंड अभियान ने गवर्नर के नाम दिया ज्ञापन

रांची. जय झारखंड अभियान नामक संगठन ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को आवेदन देकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसाओं पर मुख्यमंत्री की मांग की है। संगठन के संयोजक सुनील कुमार महतो ने कहा है कि सूचना आयुक्त के लिए अनुशंसित नामों में राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। प्रावधान के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हो सकते। आवेदन में न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और गैर-राजनीतिक रखने की बात कही गयी है। संगठन ने राज्यपाल से अनुशंसाओं की स्वतंत्र व गहन जांच कराने की मांग की है।

विष्णुगढ़ घटना पर अंबा प्रसाद ने बताया आक्रोश

रांची. पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने विष्णुगढ़ पहुंचकर दुःखमं व हत्या की शिकार 12 वर्षीय बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर आक्रोश जताते हुए इसे निर्भया कांड से भी अधिक दर्दनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस-प्रशासन की विफलता है। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। हजारीबाग पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होने की अपील की।

आठवीं अनुसूची में शामिल हो कुड़माली : चंद्रप्रकाश

रांची. गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोकसभा में कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और इस भाषा को बोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कदम भाषा के सम्मान, संरक्षण और विकास के लिए बेहद जरूरी है। सांसद ने कहा कि कुड़माली केवल एक भाषा नहीं, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों लोगों की पहचान, संस्कृति और परंपरा का आधार है। यह भाषा सदियों से लोकगीत, लोक कथाओं और सामाजिक जीवन की समृद्ध विरासत को संजोये हुए है। उन्होंने कहा कि आठवीं अनुसूची में शामिल होने से भाषा को सरकारी मान्यता मिलेगी, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग बढ़ेगा तथा आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ी रहेंगी। श्री चौधरी ने कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अवधारणा तभी सार्थक होगी, जब देश की सभी भाषाओं को समान सम्मान मिले। कुड़माली भाषी लंबे समय से संवैधानिक मान्यता की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की।

छात्रवृत्ति के अभाव में गरीब छात्र परेशान : जयराम

रांची. दुमरी विधायक जयराम महतो ने रांची में रिम्प के विस्तार कार्य को जल्द शुरू करने और संताल परगना में नेतरहाट की तर्ज पर विद्यालय स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन उसे धरातल पर उतरने में देरी हो रही है, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में मौजूदा मुख्यमंत्री आवास के रखरखाव और मरम्मत पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। उन्होंने मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा : सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए सघर्ष कर रही है और छात्रवृत्ति के अभाव में गरीब छात्र परेशान हैं। मुख्यमंत्री के नये आवास निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 67 करोड़ रुपये से नये मुख्यमंत्री आवास का निर्माण किये जाने पर भी सवाल उठाये। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस राशि को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाये।

सहायक वन संरक्षक परीक्षा के लिए कल से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड

रांची. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा सहायक वन संरक्षक के 78 पद पर चार से 12 अप्रैल तक नियुक्ति परीक्षा होगी। इसमें शामिल होनेवाले अभ्यर्थी 29 मार्च से एडमिट कार्ड व उपस्थिति प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालकर वेबसाइट से एडमिट कार्ड व उपस्थिति प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को अगर डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो वे तीन अश्लिषक अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड आयोग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से दिन के 12.30 बजे तक तथा

द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक व आइआरआईएस के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। ऐसे में पहली पाली के अभ्यर्थियों को सुबह आठ बजे तक तथा द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों को दोपहर एक बजे तक केंद्र पहुंचना जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को केंद्र पर एडमिट कार्ड व उपस्थिति प्रपत्र के साथ चार रीगन पासपोर्ट साइज फोटो व वैध पहचान पत्र लेकर आना होगा। मोबाइल, गैजेट्स, कैलकुलेटर, किताब, नोट्स आदि लाना मना है। अभ्यर्थी को सभी पत्रों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। प्रत्येक पाली के लिए अभ्यर्थी को एक ही उत्तरपुस्तिका मिलेगी। मुख्य परीक्षा के लिए पीटी में 1110 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें : हेमंत

मुख्यमंत्री हेमंत ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में की पूजा

प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। सामाजिक सद्भाव और समरसता के साथ रामनवमी महापर्व को ऐतिहासिक और यादगार बनायें। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे रामनवमी पर पत्नी कल्पना सोरेन के साथ श्री राम जानकी मंदिर तपोवन पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूजा की और राज्य के लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यहां आकर हमें काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आस्था के समागम में शामिल होने का मिला सौभाग्य : सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रामनवमी महापर्व के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी आस्था के समागम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहां पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। विभिन्न अखाड़ों की शोभायात्रा का आज यहां समागम हो रहा है। तपोवन मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसकी एक अलग पहचान है। अब इसी पहचान को और मजबूत बनाने की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया है। मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। हम सभी भगवान श्री राम से कामना करें कि इस मंदिर को बचवा देने का काम जल्द से जल्द पूर्ण हो। इससे पहले मंदिर के महंत ओम प्रकाश शरण ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पूजा करायी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे, श्री महावीर मंडल के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह यादव आदि ने भी सीएम का स्वागत किया। सीएम आवास में की पूजा : इसके पूर्व हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन ने सीएम आवास (कांके रोड) स्थित हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजा की।



पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर में पूजा करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ में कांग्रेस नेता आलोक दुबे व अन्य.

उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन के साथ भेजा पत्र

मेंटल हेल्थ व आत्महत्या रोकथाम उपायों पर विवि से मांगी गयी रिपोर्ट

विशेष संवाददाता, रांची

राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी विवि से 10 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है कि उनके यहां मेंटल हेल्थ व आत्महत्या रोकथाम के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं। सरकार के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने इस बाबत गाइडलाइन के साथ पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रिम कोर्ट के निर्देश के आलोक में सभी विवि, सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों में मेंटल हेल्थ व आत्महत्या रोकथाम के उपाय अनिवार्य रूप से किया जाना है। निदेशक ने सभी विवि से इस बाबत 10 अप्रैल तक संबंधित दस्तावेज के साथ विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निदेशक द्वारा भेजी गयी गाइडलाइन के निर्देशों का अनुपालन भी करने की बात कही है। निदेशक के अनुसार ये दिशानिर्देश तब तक प्रभावी और बाध्यकारी रहेंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई उपयुक्त कानून या नियामक ढांचा लागू नहीं कर दिया जाता है।

10 अप्रैल तक विश्वविद्यालयों को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विद्यार्थियों के जाने पर रोक लगायें

सरकारी और निजी विवि को भेजी गयी गाइडलाइन में हिदायत दी गयी है कि सभी आवासीय-आधारित शैक्षणिक संस्थान परिसर में नशीले पदार्थों और अन्य हानिकारक पदार्थों का सेवन नहीं हो। छात्रावास में छेड़छाड़ नहीं होनेवाले सीलिंग पंखे या समकक्ष सुरक्षा उपकरण लगायें। विद्यार्थियों के छत्र, बालकनी तथा अन्य उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंचने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि आत्म-हानि के आयोगपूर्ण कृत्यों को रोक जा सके। जिन शैक्षणिक संस्थानों में 100 या उससे ज्यादा छात्र नामांकित हैं, वहां कम से कम एक योग्य काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करें। छात्रों के छोटे समूहों के लिए समर्पित मंटर या काउंसलर नियुक्त होंगे। विवि, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर बंद अलग करने, सार्वजनिक रूप से शर्मिंद करने या छात्रों की क्षमताओं से ज्यादा शैक्षणिक लक्ष्य देने से बचना होगा। आत्महत्या हेतुपलाइन नंबर, जिनमें टेली मानस और अन्य राष्ट्रीय सेवाओं की जानकारी छात्रावासों, कक्षाओं और वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।

एसटी-एससी, ओबीसी और दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं हो

संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षक, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी हाथियों पर पड़े पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं के साथ संवेदनशील, समावेशी और बिना किसी भेदभाव के साथ व्यवहार करेंगे। इनमें विशेष रूप से एसटी/एससी/ओबीसी, इडब्ल्यूएस, आदिम जनजाति समुदायों के छात्र, दिव्यांग छात्र, घर से बाहर देखभाल में रहनेवाले छात्र, और शोक, आघात या पहले के आत्महत्या के प्रयासों से प्रभावित छात्र शामिल होंगे। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों को जाति, वर्ग, लिंग, दिव्यांगता, धर्म या जातीयता के आधार पर होनेवाले यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, रैगिंग और धमकाने की घटनाओं की रिपोर्ट करने, उनके निवारण और रोकथाम के लिए मजबूत, गोपनीय और सुलभ तंत्र स्थापित करने होंगे। प्रत्येक संस्थान एक आंतरिक समिति या नामित प्राधिकारी का गठन करेंगे, जिस पर शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होगी। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में माता-पिता और अभिभावकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा

सभी शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक के अलावा पाठ्येतर गतिविधियों को प्राथमिकता देंगे, इनमें खेल, कला, और व्यक्तित्व विकास की पहल शामिल होंगे। शैक्षणिक बोझ को कम करने और छात्रों में टेस्ट स्कोर और रैंक से परे पहचान की एक व्यापक भावना विकसित करें।

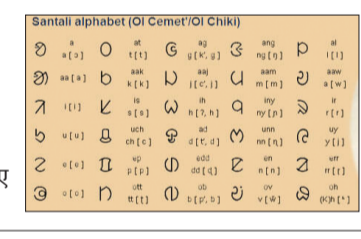
यूपीएससी : संताली विषय की कोचिंग करायेगी राज्य सरकार

प्रमुख संवाददाता, रांची

झारखंड सरकार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को संताली (वैकल्पिक) विषय की निःशुल्क कोचिंग करायेगी। इस संबंध में डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोचिंग का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाना है। कोचिंग के लिए 50 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। कोचिंग के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता तय कर दी गयी है। इसके लिए

कोचिंग के लिए 50 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा

- डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान करेगा कोचिंग का संयोजन
- कोचिंग समन्वयक व अतिथि शिक्षक के लिए भी मांगे गये आवेदन



डायट में नामांकन के लिए 18 तक जमा होगा आवेदन

रांची. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक नीलम आईलीन टोपो ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। संस्थान में नामांकन के लिए विद्यार्थी 18 अप्रैल तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन सही ढंग से माध्यम से क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिणी प्रमंडल को भेजना है। आवेदन प्राप्त का समय 18 अप्रैल की शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है।

नये सचिवालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से मांगा सहयोग

प्रमुख संवाददाता, रांची

झारखंड सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए नये सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 16वें वित्त आयोग से विशेष वित्तीय सहयोग मांगा है। यह प्रस्ताव राज्य द्वारा आयोग के समक्ष रखी गयी 3.03 लाख करोड़ की समग्र वित्तीय सहायता मांग का अहम हिस्सा है। सरकार का मानना है कि वर्तमान सचिवालय भवन बढ़ती प्रशासनिक

जरूरतों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। ऐसे में रांची में एक अत्याधुनिक, सुविधायुक्त और समर्पित सचिवालय का निर्माण जरूरी है, जहां विभिन्न विभाग एक ही परिसर में कार्य कर सकें। इससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और दक्षता बढ़ेगी। नये सचिवालय के निर्माण को राज्य के दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष यह तर्क रखा कि मजबूत प्रशासनिक ढांचा राज्य के समग्र विकास की आधारशिला होता है। राज्य

सरकार ने 16वें वित्त आयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन, उन्नत प्रभावित क्षेत्रों के विकास और आदिवासी सशक्तीकरण के लिए भी वित्तीय सहयोग की मांग की है। जानकारी के अनुसार, आयोग ने राज्य की मांगों पर विचार करते हुए वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दिया है। राज्य सरकार को स्थानीय निकायों को मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देने की सलाह दी गयी है।

एचडसी स्थित कोर कैपिटल एरिया में 150 करोड़ से यूनिटी मॉल और 44 करोड़ से हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यूनिटी मॉल का निर्माण 50% पूरा

विशेष संवाददाता, रांची

रांची के एचडसी स्थित कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। दोनों का निर्माण कायं लगभग 50 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। 150 करोड़ (केंद्र व राज्य सरकार के फंड से) से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक-एक यूनिटी मॉल की स्वीकृति दी थी। यूनिटी मॉल में राज्य के चिह्नित एक जिला एक उत्पाद के स्टॉल होंगे। इसके अलावा देश के सभी राज्यों के चिह्नित एक-एक जीआइ टैग वाले उत्पाद के

स्टॉल भी होंगे, जो बिक्री व प्रदर्शनों के लिए उपलब्ध रहेंगे। यहां खान-पान के अलावा हस्तशिल्प व अन्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। झारखंड की सोहराई व कोहबर पेंटिंग को जीआइ टैग मिला है। वहीं, बिहार के जर्दलु आम, लूची व मखाना, ओडिशा के सुगुल्ला व हिमाचल के चंबा चपल जैसे जीआइ टैग प्राप्त उत्पाद इस मॉल में रखे जायेंगे। यूनिटी मॉल के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परियोजना की ही चयन किया गया है। 3.5 एकड़ के इस परिसर में एक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व दूसरी और यूनिटी मॉल बन रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मिलेगी सुविधा

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण राज्य में स्थित उद्योगों व व्यापार द्वारा आयात-निर्यात के लिए किया जा रहा है। सेंटर के भवन में निर्यात करने वाली कंपनियों के कार्यालय, सेमिनार व प्रदर्शनों के लिए हॉल भी बनाने का प्रस्ताव है। भवन में ही निर्यात करने वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहां विदेशी व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिषद से जुड़े



कार्यालय भी होंगे। साथ ही करेसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं होंगी। एक्सपोर्ट लाइसेंस

आदि देने की सुविधा भी दी जायेगी। साथ ही पेटेंट कराने की सुविधा भी दी जायेगी।

6 | संपादकीय | कल्पमेधा

जनसत्ता | 28 मार्च, 2026

जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है, पर उसमें खुशबू नहीं है। ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं, अगर वह उनको अमल में नहीं लाता।

– महात्मा बुद्ध

दहेज का दंश

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद दहेज के लिए विवाहिता की हत्या या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। इक्कीसवीं सदी में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने के बावजूद इस मामले में समाज के एक हिस्से की रूढ़िवादी मानसिकता नहीं बदली है। यही नहीं, कानूनों को सख्ती से लागू करने के मामले में भी विभिन्न स्तरों पर लापरवाही देखी जाती है, जिस कारण इस कुप्रथा की जड़ें नष्ट होने के बजाय गहरी होती जा रही हैं। इसका दंश महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी जान पर भी भारी पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में इस पर गहरी चिंता जताई और दहेज के मामलों में महिलाओं की मौत की घटनाओं को समाज पर गहरा धब्बा करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस सामाजिक कुरीति के कारण आज भी हजारों महिलाएं बेमैत मारी जाती हैं।

सरकारी स्तर पर देश में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इसकी वास्तविक तस्वीर बेहद चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2023 में दहेज संबंधी अपराधों के तहत दर्ज मामलों में चौदह फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में इससे संबंधित पंद्रह हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें छह हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत हो गई। जबकि वर्ष 2022 और 2021 में यह संख्या क्रमशः 13,479 और 13,568 थी। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या वजह है कि दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वालों में कानून का जरा भी खीफ नहीं है! इसके लिए निश्चित तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ढुलमुल रवैया भी जिम्मेदार है। पुलिस की लापरवाही की वजह से कई बार दहेज से संबंधित मामलों के आरोपी अदालत में सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। कई दफा पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

दहेज प्रथा केवल सामाजिक बुराई ही नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और गरिमा का भी गंभीर उल्लंघन है। मगर कई मामलों में पीड़ित महिलाओं के परिरज कानूनी जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव के कारण पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाते। ऐसे में इस बात पर गहवाई से विचार करने की जरूरत है कि क्या भौतिक वस्तुएं, पैसा और झूठी शान किसी महिला की जान से ज्यादा मूल्यवान है! इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि दहेज उत्पीड़न या हत्या के मामलों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर उनकी गहन जांच की जाए। इस तरह के मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता और अन्य पहलों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जैसे महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा बेटियों को लेकर समानता आधारित दृष्टिकोण को धरातल पर सही मायने में अमल में लाना। सच यह है कि कानूनी सख्ती के समंतर जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक किसी भी कुरीति को पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं है।

लापरवाही बदस्तूर

पिछले कुछ समय से सफर के दौरान ट्रेनों में यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने की शिकायतें सुर्खियों में रही हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद भारतीय रेल की ओर से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में बेहतर सेवा देने के आश्वासन दिए जाते हैं। मगर ऐसा लगता है कि संबंधित महकमों को ट्रेनों में खराब खाना देने की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसमें सुधार करने की कोई फिक्र नहीं है। वरना क्या वजह है कि जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तब रेलवे के अधिकारी या मंत्रालय थोड़ा सक्रिय दिखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही दशा आम हो जाती है। हालत यह है कि वंदे भारत जैसी जिन ट्रेनों को उच्च और प्रीमियम दर्जे की सुविधाओं से लैस बताया जाता है, उनमें भी खराब खाने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। गौरतलब है कि पटना-टायनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री ने खाने में परोसे गए दही में कीड़ा होने की शिकायत की। आसपास मौजूद अन्य यात्रियों के साथ-साथ इसका वीडियो फैलने के बाद आम लोगों के बीच इस बात पर नाराजगी बढ़ी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने लापरवाही बरतने पर आइआरसीटीसी पर दस लाख रूपए का जुर्माना लगाया, वहीं उस ट्रेन में खानपान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पर पचास लाख रूपए का जुर्माना लगाने के साथ-साथ अनुबंध खत्म करने का भी आदेश दिया।

इस तरह का यह कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले वर्ष जुलाई में खुद रेल मंत्रालय ने संसद को बताया था कि 2024–25 के दौरान ट्रेनों में खराब खाने को लेकर 6,645 शिकायतें दर्ज की गई थीं। ऐसे मामले भी होते होंगे, जिनमें किसी यात्री को मिला खाना खराब होता होगा, लेकिन वे औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराते होंगे। सवाल है कि खानपान की गुणवत्ता को हर तरह से स्वच्छ और बेहतर बनाने का रेल महकमे का ढांचा आखिर कैसे काम करता है कि आए दिन यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने के मामले सामने आते हैं। क्या यह यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? रेल मंत्रालय की ओर से कई बार सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन बार-बार ऐसी शिकायतों के बावजूद इस समस्या पर लगाम लगाना मुश्किल क्यों बना हुआ है!

संभावनाओं और चुनौतियों के बीच चांद

अमेरिका और चीन चांद को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों, संसाधनों पर वर्चस्व और तकनीकी बढ़त का आधार बनाना चाहते हैं। निजी कंपनियां भी इस दौड़ में उतर चुकी हैं, जिससे अंतरिक्ष अब सरकारों तक सीमित न रह कर आम आदमी के भविष्य से जुड़ा जा रहा है।

विजन कुमार पांडेय

अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच शक्ति और वर्चस्व की नई जमीन बन चुका है। इस बदले दौर में चांद एक बार फिर रणनीतिक होड़ का केंद्र बन गया है। अमेरिका और चीन चांद को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों, संसाधनों पर वर्चस्व और तकनीकी बढ़त का आधार बनाना चाहते हैं। निजी कंपनियां भी इस दौड़ में उतर चुकी हैं, जिससे अंतरिक्ष अब सरकारों तक सीमित न रह कर बाजार, रोजगार और आम आदमी के भविष्य से जुड़ता जा रहा है। चांद पर जाने की यह जल्दबाजी केवल विज्ञान की जिज्ञासा नहीं, बल्कि आने वाले समय में ताकत की रूपरेखा तय करने की तैयारी है। जो देश आज चांद पर अपनी मौजूदगी मजबूत करेंगे, वही कल अंतरिक्ष से जुड़ी कमाई और बड़े फंसलों पर असर डालेंगे। ऐसे में भारत के सामने भी सवाल है कि क्या वह इस बदलती अंतरिक्ष राजनीति को समझ कर समय रहते अपनी योजना बनाएगा?

मनुष्य सबसे पहले मंगल पर कब पहुंचेगा, यह सवाल लंबे समय तक रोमांच बना रहा। 'स्पेसएक्स' और 'ब्लू ओरिजिन' ने इसी सपने को अपनी पहचान बनाया। एलन मस्क समय सीमा घोषित करते रहे। उद्देश्य था- महत्वाकांक्षा दिखाना और प्रतिभा आकर्षित करना। मगर हाल के महीनों में तस्वीर बदली है। हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे 'स्पेसएक्स' लंबे समय से नासा के साथ चांद से जुड़े काम में लगी थी। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मानव को चांद पर उतारने का जिम्मा इसी का प्रमाण है। उधर, जेफ बेजोस की कंपनी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि अंतरिक्ष की अगली निर्णायक मंजिल मंगल नहीं, बल्कि चांद है।

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नासा की बदलती प्राथमिकताएं हैं। अमेरिका का आर्टेमिस कार्यक्रम चांद पर स्थायी उपस्थिति बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यह केवल वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की नींव रखने का प्रयास है। चांद पर खनिज संसाधन और ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम कर सकता है। साथ ही अमेरिका को यह चिंता भी सता रही है कि यदि उसने चांद पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, तो चीन यह बढ़त हासिल कर लेगा। उसने चांद पर कई सफल मिशन भेजे हैं और वह 2030 के लिए मानव मिशन की घोषणा कर चुका है।

भारत के लिए इस वैश्विक बदलाव में कई गहरे संकेत छिपे हैं। चंद्रयान-3 के माध्यम से उसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतर कर यह दिखा दिया कि वह केवल अंतरिक्ष दौड़ का दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय खिलाड़ी है। यह क्षेत्र इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि यहां जल और बर्फ के मौजूदगी की संभावना है, जो भविष्य में ईंधन, आक्सीजन और मानव बस्तियों की आधारशिला बन सकती है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में है जिनके पास चांद तक पहुंचने और वहां उतरने की क्षमता है। यह सफलता केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति का संकेत भी है। इससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और इसरो को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर मिले हैं।

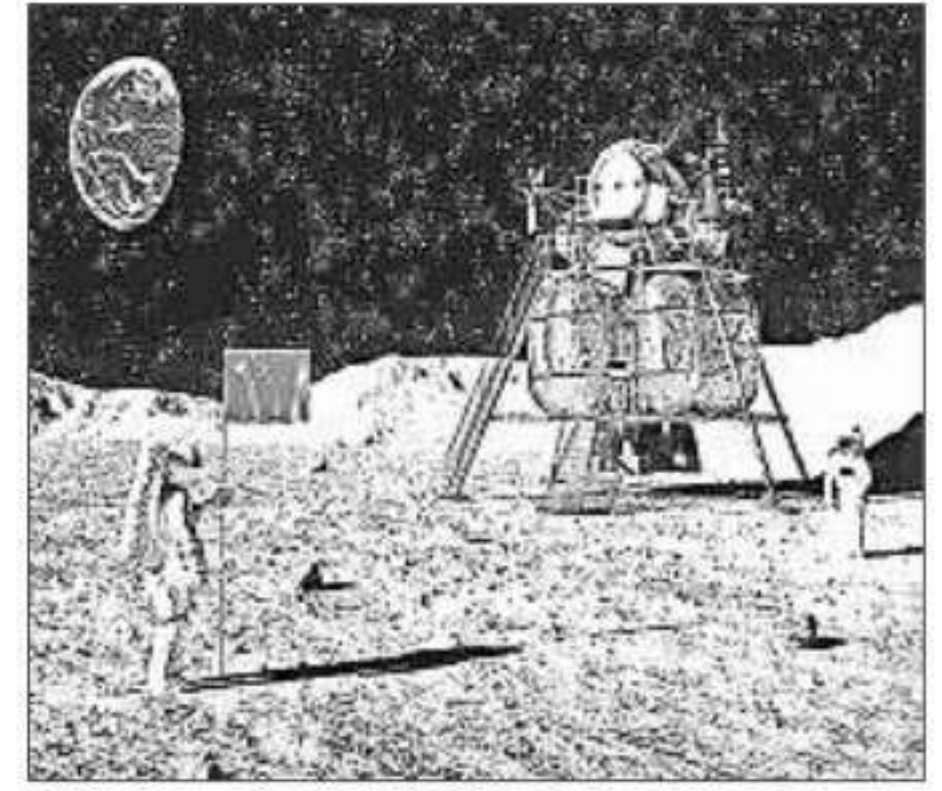
आनंद के ठौर

मनीषा मंजरी

हमारा यह जीवन केवल सांसों का नियमित प्रवाह नहीं है, बल्कि अनुभवों, भावनाओं और चेतना की एक गहन यात्रा भी है। इस यात्रा में सामान्यतः सुख और दुख, आशा और निराशा, संघर्ष और विश्राम सब एक साथ चलते रहते हैं। पर आधुनिक जीवन की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताओं ने हमारे मन को इतना व्याकुल कर दिया है कि हम जीवन के वास्तविक सौंदर्य और आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का अधिकांश भाग चिंता, तनाव और असंतोष से भरा हुआ है। मगर गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि मनुष्य का जीवन केवल चिंता और तनाव के लिए नहीं है, बल्कि आनंद, आशा और संतुलन के लिए भी है। जीवन की कठिनाइयों हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमारे भीतर के उत्साह और आशा को समाप्त करना नहीं होता।

जब हम जीवन को केवल समस्याओं और संघर्षों की शृंखला मान लेते हैं, तब हम अपने ही भीतर के आनंद के स्रोत से दूर हो जाते हैं, लेकिन जीवन को एक व्यापक चेतना की प्रक्रिया के रूप में देखें, तो हमें अनुभव होगा कि चिंता और तनाव जीवन के अंतिम सत्य नहीं हैं। उनके साथ-साथ आनंद, आशा और संतुलन भी जीवन के अभिन्न आयाम हैं। हमारा मन स्वभावतः चंचल होता है। यह या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की आशंकाओं में स्वयं को भटकता रहता है। इसी कारण वर्तमान क्षण की सहजता और सुंदरता हमसे अक्सर छूट जाती है। चिंता का मूल भी यही है, वह उस समय पैदा होती है, जब मन वर्तमान से दूर हो जाता है। दर्शनों की दृष्टि से देखा जाए, तो जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान में ही संभव है। जब हमारा मन वर्तमान के इस क्षण को स्वीकार करता है और उसमें उपस्थित छोटी-छोटी खुशियों को पहचानता है, तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है।

अक्सर हम यह मान बैठते हैं कि सुख केवल बड़ी-बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में निहित है, जैसे प्रतिष्ठा, संपत्ति या सफलता में। मगर यह विचार अधूरा है। जीवन का गहन आनंद और सुंदर बन सकता है। इस प्रकार जीवन को केवल चिंता और तनाव के रूप में देखना उसके व्यापक अर्थ को सीमित कर देना है। जीवन एक ऐसी यात्रा है, जिसमें आनंद, आशा, संघर्ष और अनुभव, सभी मिलकर हमारे अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हम जीवन को केवल जीते ही नहीं, बल्कि उसे गहराई से अनुभव भी करते हैं।



असली परीक्षा वैज्ञानिक या तकनीकी नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्रश्न यह नहीं कि भारत चांद तक पहुंच सकता है या नहीं। यह तो वह सिद्ध कर चुका है। असली प्रश्न यह है कि क्या भारत इस सफलता को ऐसी दीर्घकालिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति में बदल पाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई

भारत ने चंद्रयान-3 के माध्यम से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतर कर यह दिखा दिया कि वह केवल अंतरिक्ष दौड़ का दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय खिलाड़ी है। यह क्षेत्र इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि यहां जल और बर्फ की मौजूदगी की संभावना है, जो भविष्य में ईंधन, आक्सीजन और मानव बस्तियों की आधारशिला बन सकती है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में है जिनके पास चांद तक पहुंचने और वहां उतरने की क्षमता है। यह सफलता केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति का संकेत भी है।

दिशा दे सके और जोखिमों को कम कर सके। क्या चांद पर नियमित मिशन भेजने, वहां उपलब्ध संसाधनों की खोज और भविष्य की औद्योगिक

संकट के बीच

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 60 फीसद से अधिक हिस्सा मध्य-पूर्व से आयात करता है और इसका एक बड़ा भाग होमुज जलमार्ग से आता है। पिछले चार सप्ताह से अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में तेल और गैस संकट बढ़ा दिया है। भीषण युद्ध और बाधित मार्गों के बावजूद, भारत के कूटनीतिक प्रयासों के कारण हमारे जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर देश पहुंच रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर कच्चे तेल और गैस की कमी की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार को नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ-साथ कठोर कदम उठाने होंगे। इस युद्ध की आड़ में कुछ लोग मुनाफाखोरी की तैयारी में हैं। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ इसी ओर संकेत करती है। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जिंला, ब्याक और ग्राम स्तर तक सख्त सौ निगरानी रखें और आपदा के समय आम जनता का शोषण करने वाले लोगों पर कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें, ताकि ऐसे तत्त्वों पर नियंत्रण रहे।

– अरविंद रावल, झाबुआ, मप्र

यात्रियों के साथ

‘समय की पाबंदी’ (संपादकीय, 26 मार्च) पढ़ा। रेल यात्रा आम आदमी की जरूरत है और मजबूरी भी। ऐसे में यदि नए नियमों के अनुसार लंबी दूरी की ट्रेनों में निर्धारित यात्रा से आठ घंटे से कम समय रह जाने पर आरक्षित टिकट रद्द कराने पर कोई किराया वापस नहीं होगा, तो यह फैसला यात्रियों के हित में कम और रेलवे के कमाई नीति अधिक प्रतीत होती है। कई बार यात्रा रद्द करना यात्री की हालती नहीं होती। अचानक बीमारी, परिवार में कोई आपात

शांति का सूत्र

पा रंपरिक मान्यता रही है कि राष्ट्रों के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता युद्ध की संभावना को कम करती है। यूरोपीय संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कोयले और स्टील के व्यापारिक गठबंधन ने कभी शत्रु रहे देशों को शांति के सूत्र में बांध दिया। मगर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, विशेषकर ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने चिंता बढ़ा दी है। ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करते समय उसकी आर्थिक शक्ति का तो सही आकलन किया गया, लेकिन उसकी

अफवाहों का जाल

अफवाह कई बार लोगों का विवेक हर लेती है। अफवाहें अदृश्य शक्ति की तरह होती हैं, लेकिन इसकी फैलाने वाले आमतौर पर शांतिर होते हैं, जिन्हें दूसरे लोगों को परेशान देखने में आनंद आता है। पिछले दिनों अफवाह उड़ी कि देश में पेट्रोल और डीजल का संकट है। यह अफवाह जैसे ही फैली, पेट्रोल-डीजल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। शोर-शरावा मचने लग गया। किसी ने सोचने समझने की जरूरत महसूस नहीं की कि पेट्रोल डीजल का फिलहाल कोई संकट नहीं है। अब अफवाहों का जब इस तरह संज्ञान लेकर लोग भागवौड़ करेंगे, तो अफवाहें फैलाने वालों को आनंद आएगा ही। इसलिए अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। असलियत जानना ही जरूरी है। दुर्भाग्य है कि कम पढ़े-लिखे ही नहीं, पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी अफवाहों के भंवरजाल में अक्सर फंस जाते हैं।

– हेमा हरि उपाध्याय, अक्षत, उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com |chaupal.jansatta@expressindia.com



भारत के निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। स्थापना के समय आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।



मेरे टूटे हौसले के पर निकलते देख कर उसने दीवारों को अपनी ओर और ऊंचा कर दिया
—आदिल मंसूरी

भारत के संविधान को उसके नागरिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि लाख बाधाओं के बावजूद लोकतंत्र पर उनकी आस्था बरकरार है और वे चुनावी प्रक्रिया में पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। गरीबी, अशिक्षा, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के बावजूद जब वे भारत के

बेबाक बोल

मतदाता बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए चुनाव आयोग अपनी दीवार और ऊंची कर दे रहा है। मतदान का दिन, नतीजों का दिन, उम्मीदवार, वादे-इरादे सब घोषित हो चुके हैं। अगर कोई काम अधूरा है तो वह मतदाता सूची का काम। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर त्रुटि हो जाती है, वह त्रुटिवश केरल भाजपा की मुहर के साथ अपना पत्र जारी कर देता है। संसाधनों से भरे संस्थान की इतनी गलतियों के बरक्स लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बचाए रखने में जुटे संसाधन विहीन नागरिकों पर बेबाक बोल।

रीढ़ की हड्डी

मुकेश भारद्वाज

‘ए’ क समय सिस्टम ने गलती से यह दिखाया कि राज्य के सभी मतदाता विचाराधीन हैं। जबकि ऐसा नहीं था, यह केवल एक त्रुटि थी। मीडिया रपटों के मुताबिक यह एक चुनाव अधिकारी का बयान है। पश्चिम बंगाल, केरल सहित पांच राज्यों में जब अप्रैल में चुनाव होने हैं, नेताओं को टिकट देने व नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब भी बंगाल में मतदाताओं का एक तबका इस बात को लेकर ‘विचाराधीन’ है कि वह ताजा चुनाव प्रक्रिया में मतदाता है या नहीं? आरोप है कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद, लगभग 60 लाख नामों को मतदाता के रूप में उनकी पात्रता की जांच के लिए अलग रखा गया है। ये राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 8.5 फीसद हिस्सा है। मौजूदा तारीख तक मतदाता सूची में इनका दर्जा बतौर ‘विचाराधीन’ है।

जब पांच राज्यों में चुनाव के नतीजों का दिन मुकर्रर हो चुका है, तब तक एक राज्य की 8.5 फीसद मतदाता का दर्जा मुकर्रर नहीं हो पाया है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को सबसे ज्यादा अधिकारों से लबरेज किया है। गणतंत्र का आधार ही नागरिकों की गणतांत्रिक शक्तियां होती हैं। लेकिन, जमीनी हकीकत यही है कि राजनीतिक दलों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं को सबसे कम परवाह इसी कि दिखती है। जिन नागरिकों, मतदाताओं से देश, संविधान, भाजपा-कांग्रेस-वाम जैसे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का वजूद है, बार-बार उन्हीं के वजूद पर सवाल उठा दिए जाते हैं।

देश की सीमाओं के अंदर घुसपैटिये आ गए हैं तो इसके लिए किसी भी तरह से नागरिक या मतदाता जिम्मेदार नहीं हैं। फिर बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव आते ही घुसपैटियों का मसला कैसे आ जाता है? राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को नागरिकता साबित करो बयान घुसपैटिया में तब्दील कर दिया। 2014 के पहले की सरकार ने ‘आधार’ परियोजना पर इस देश के संसाधन का बड़ा हिस्सा खर्च किया। बाद की मौजूदा सरकार ने भी सभी सरकारी सेवाओं को आधार से जोड़ा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसे निराधार साबित करने की पूरी कोशिश की गई।

बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के विरोध-प्रदर्शन से लगा था कि इस गहन पुनरीक्षण में वह तो जनता का गहनता से साथ देगा। बाद में यह भी वैसा ही हंगामा निकला, जिसमें सूरत बदलने की कोई कोशिश नहीं थी। अदालत में पता चला कि एक दो राजनीतिक दलों के अलावा किसी दल ने मतदाता सूची से खारिज की जा रही जनता को लेकर अदालत पहुंचने में रुचि नहीं ली।



चुनाव आयोग के लिए तकनीकी त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि कहते हुए पल्ला झाड़ कर निकल जाना जितना आसान है, क्या यह आम नागरिकों के लिए भी उतना ही आसान है? आम नागरिक ने अपने दस्तावेज दिए और जिम्मेदार संस्था ने गलत नाम लिख दिया। अब वो मतदाता नहीं ‘विचाराधीन’ है। वहीं केरल में चुनाव आयोग के कार्यालय ने जो पत्र जारी किया, उस पर भाजपा की केरल इकाई की मुहर लगी हुई थी। आयोग ने माना कि यह गलती थी और इसके लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को निलंबित भी किया गया। कहा गया कि भाजपा के द्वारा दाखिल

दस्तावेज ही प्रत्युत्तर में शामिल कर दिए गए थे। अब इस गलती को एक तथ्य के रूप में माना जा रहा है। लेकिन गलती के दोनों पक्ष मजेदार हैं। गलती करने का आरोप चुनाव आयोग पर, और मुहर केरल भाजपा की। मुहर तो किसी भी सत्ता और उसके दस्तावेज का इकबाल होती है। इसलिए आपकी इस गलती को इतनी साधारण नहीं माना गया और पूरे देश में संशय फैला। इस संशय के पर्याप्त कारण थे। पिछले हुए चुनावों में आयोग पर आरोप लगे कि आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए तो वह खट्टा-मीठा अचार सा है, जिसे खिचड़ी के साथ खाए या फिर

पराटे के साथ। सत्ता-पक्ष के नेताओं के आचार संहिता को तार-तार करने वाले दुश्च सोशल मीडिया पर आम होने लगे तो बीच खेल में चुनाव आयोग ने संहिता ही बदल दी, और राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस भेजने की भी शुरुआत कर डाली।

पिछले चुनाव के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका ‘माताओं-बहनों के वीडियो’ वाला तारीखी तर्क भी याद है, जहां आपने देश के नागरिकों और उनके अधिकारों का लैंगिक वर्गीकरण कर दिया था। आजाद भारत के संविधान ने अपने निर्माण के साथ ही महिला और पुरुष दोनों को नागरिक मानते हुए एक जैसे मताधिकार दिए, लेकिन जब मताधिकार की हकमारी पर सवाल हुए तो आपने संवैधानिक अधिकारी नहीं बल्कि किसी सामंती घर-परिवार के पुरुष मुखिया वाला तर्क प्रस्तुत कर दिया।

चुनाव को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। वहीं निष्पक्ष मतदाता सूची को चुनाव का आधार माना जाता है। मतदाता सूची देश के उन्हीं नागरिकों से बनती है जिसका एक बड़ा तबका बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझ रहा है। उसे हर रोज अपनी अशिक्षा और व्यवस्था के भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है। बिहार में देखा गया था कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि में दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया के दौरान ही भ्रष्टाचार के कई गुणा बढ़ जाने के आरोप लगे। अपना नाम मतदाता सूची में देखने के लिए प्रवासी कामगारों को कई दिन की छुट्टी लेकर अपने गृह-प्रदेश में मौजूद रहना पड़ता था। स्त्रियां अपने दस्तावेज के लिए मायके की खाक छान रही थीं।

इन मतदाताओं में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सरकार के लिए मुफ्त राशन पर निर्भर है। हमारी सरकार इनकी संख्या अस्सी करोड़ बताती है। चुनाव आयोग खुद ही अंदाजा लगाए कि यह भारत के कुल मतदाताओं का कितना फीसद होगा? जिस तबके की पहुंच जीवन निर्वाहक बुनियादी चीजों तक नहीं है, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी इंटरनेट तक पहुंच हो, उनकी तरफ से सब दुस्तुद है। वो आपके एक फरमान पर, आपकी दी हुई तारीख तक सब दुरुस्त करवा लें और आप अपने कार्यालय से निकले कागज तक की निगरानी नहीं रख पाए कि उस पर मुहर किसकी है। आप चुनाव की तारीखों के एलान के बाद भी अपने कागज और मतदाताओं को ‘विचाराधीन’ रख दें।

मतदाता और मतदाता सूची चुनाव की रीढ़ हैं। देश के संविधान को यहां के नागरिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हीं को खचाए रख कर कई मुसीबतें झेल कर गणतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को बचाए रखा है। अपनी मजदूरी कटवा कर, घंटों कतार में खड़े रह कर, भीड़ भरी ट्रेन में सफर करके वह देश की संवैधानिक, गणतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े रहना चाहता है। इस देश का लोकतंत्र उन नागरिकों के भरोसे बचा है, जो आपके पक्षपात के इतने आरोपों, इतनी गलतियों को नजरअंदाज कर मतदान करने निकलेगा। चुनाव आयोग से अनुरोध है, कृपया इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम नहीं कीजिए। गलतियां थोड़ी कम कीजिए। आपकी गलतियां लोकतंत्र की रीढ़ पर भारी पड़ती हैं।

सांसद नाम के

रं जन गोगोई इसी महीने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए। गोगोई देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रधान न्यायाधीश थे। जहां से वे 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले पांच जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। सुप्रीम कोर्ट की एक महिला अधिकारी ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था, जिसकी उन्होंने खुद एक

तीन सदस्यीय आंतरिक समिति बनाकर जांच कराई थी। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के छह माह बाद जब केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया था, तो खासा विवाद खड़ा हुआ था। आलोचकों ने इसे सरकार से लाभ लेना बताया था। यहां तक कि जब 17 मार्च 2019 को उन्होंने शपथ ली तो उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों ने उनके विरोध में नारेबाजी भी की थी। गोगोई ने तब अपने मनोनयन का यह कहकर बचाव किया था कि वे संसद में न्यायपालिका का पक्ष रखेंगे और उत्तर-पूर्व की समस्याओं को उठाएंगे। पर राज्यसभा का रिकार्ड बताता है कि उन्होंने छह साल में एक भी सवाल नहीं पूछा, कोई निजी विधेयक भी पेश नहीं किया। हाजिरी भी उनकी औसत से काफी कम रही। मनोनयन के तीन साल बाद सिर्फ पहली और आखिरी बार एक ही चर्चा में भाग लिया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए दिल्ली की दर्ज में किए गए बदलाव से जुड़े विधेयक पर थी।

मैदान में बागी

अ सम के पुराने भाजपा नेता पार्टी के कांग्रेसीकरण से तो पहले ही परेशान थे, टिकट बंटवारे के बाद उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता बतौर बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद बोरदेलाई भाजपा में शामिल हुए, और उन्हें टिकट भी मिला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भी भाजपा में आए और उन्हें टिकट मिला। पुराने भाजपाई लगातार खुलासा कर रहे हैं कि गठबंधन में भाजपा असम की 126 सीटों में से जिन 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से 28 पर उम्मीदवार कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। सरमा का कहना है कि 90 सीटों के विपरीत पार्टी को कुल 1400 आवेदन मिले थे। हर आवेदक को टिकट दिया नहीं जा सकता। उनका दावा है कि वे बागियों को मना लेंगे पर चुनाव में ज्यादा वतव नहीं है सो देखा है, कितने बागी मैदान से हटने को राजी होंगे।

मैदान में बागी

अ सम के पुराने भाजपा नेता पार्टी के कांग्रेसीकरण से तो पहले ही परेशान थे, टिकट बंटवारे के बाद उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता बतौर बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद बोरदेलाई भाजपा में शामिल हुए, और उन्हें टिकट भी मिला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भी भाजपा में आए और उन्हें टिकट मिला। पुराने भाजपाई लगातार खुलासा कर रहे हैं कि गठबंधन में भाजपा असम की 126 सीटों में से जिन 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से 28 पर उम्मीदवार कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। सरमा का कहना है कि 90 सीटों के विपरीत पार्टी को कुल 1400 आवेदन मिले थे। हर आवेदक को टिकट दिया नहीं जा सकता। उनका दावा है कि वे बागियों को मना लेंगे पर चुनाव में ज्यादा वतव नहीं है सो देखा है, कितने बागी मैदान से हटने को राजी होंगे।

राजपाट

लंबे सवाल, छोटे जवाब

सं सद के सत्र में सांसद अधिक से अधिक सवाल पूछ सकें, इसके लिए खूब प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इसका असर बेनेतीजा ही नजर आ रहा है। कई बार तो सवाल लंबे और जवाब छोटे नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल ही में संसद सत्र में भी नजर आया है। एक बड़े मंत्री खुल कर बोले, जबकि उनकी सहयोगी मंत्री को बार-बार लंबे जवाबों को छोटे करने के लिए कहा गया। मंत्रियों पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सख्त नजर आए। सदन का समय बचाने के लिए मंत्रियों तक के जवाब पर सख्त लहजे में कम शब्द में पूरी बात करने की नसीहत दी। यही नहीं, बार-बार अनुमति देने के बाद सांसदों द्वारा बोले जाने वाले धन्यवाद अध्यक्ष महोदय शब्द तक को भाषण से हटाने के आदेश दे दिए।

क्षेत्रीय दलों का दबदबा

त मिलनाडु के दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दल द्रमुक और अन्ना द्रमुक राष्ट्रीय दलों के दबाव में नहीं आए। पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्ना द्रमुक ने भाजपा को पिछले चुनाव की तुलना में सात सीटें ज्यादा दी पर उसकी पसंद की नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा तमिलनाडु में 20 सीटों पर लड़ी थी, पर उसे केवल चार सीटों पर ही जीत मिली थी। इसी तरह द्रमुक ने कांग्रेस को 25 सीटें दी थी, जिनमें से कांग्रेस 18 सीटों पर जीत गई थी। इस बार कांग्रेस अधिक सीटें मांग रही थी, पर एमके स्टालिन ने उसे केवल 28 सीटें दीं। अन्ना द्रमुक में पार्टी के कई नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने पलानीस्वामी को नेता बनवाया और पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम जैसी पार्टियों को गठबंधन में शामिल कराया। लेकिन पलानीस्वामी ने 234 में से 169 सीटें अपनी पार्टी के लिए रखी हैं। अबुमणि रामदास की पीएमके को 18, जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस को सात और टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम को भी कम सीटें दीं हैं। भाजपा को उसकी पसंद की सीटों ने देकर पलानीस्वामी ने अपना दबदबा कायम रखा है।

जोखिम क्यों?

बि हार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जद (एकी) ने यादों से पूरी तरह किनारा किया था। अपने यादव नेताओं को टिकट भी नहीं दिए थे। यहां तक कि नंद किशोर यादव और राम सूरत राज जैसे कद्दावर नेताओं तक को टिकट नहीं दिया। अब जनता दल (एकी) ने अपने यादव सांसद गिरधारी यादव को खलनायक बना दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर लोकसभा अध्यक्ष को उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पत्र लिखा है। वे बांका सीट से सांसद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को राजद का विधानसभा टिकट दिलवाया था। गिरधारी यादव का कहना है कि विदेश में शिक्षित उनका बेटा अपने फेसले लेने को स्वतंत्र है। दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने बिहार में एसआइआर प्रक्रिया की आलोचना की थी। जहां तक पहले आरोप का सवाल है तो नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी ने भी लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर में कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा था। अपने मंत्री पर तो नीतीश ने कोई कार्रवाई की नहीं। एसआइआर की आलोचना दस महीने पहले की घटना है। उसके बहाने अब कार्रवाई का क्या औचित्य? बहरहाल, गिरधारी यादव की सदस्यता छीनी तो बांका में उपचुनाव होगा। राजग की संस्था एक कम हो जाएगी। उपचुनाव में जीत की क्या गारंटी। सो दुविधा भाजपा को है कि क्यों जोखिम लिया जाए। शायद इसलिए गिरधारी यादव अभी बचे हैं।

क्षेत्रीय दलों का दबदबा

त मिलनाडु के दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दल द्रमुक और अन्ना द्रमुक राष्ट्रीय दलों के दबाव में नहीं आए। पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्ना द्रमुक ने भाजपा को पिछले चुनाव की तुलना में सात सीटें ज्यादा दी पर उसकी पसंद की नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा तमिलनाडु में 20 सीटों पर लड़ी थी, पर उसे केवल चार सीटों पर ही जीत मिली थी। इसी तरह द्रमुक ने कांग्रेस को 25 सीटें दी थी, जिनमें से कांग्रेस 18 सीटों पर जीत गई थी। इस बार कांग्रेस अधिक सीटें मांग रही थी, पर एमके स्टालिन ने उसे केवल 28 सीटें दीं। अन्ना द्रमुक में पार्टी के कई नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने पलानीस्वामी को नेता बनवाया और पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम जैसी पार्टियों को गठबंधन में शामिल कराया। लेकिन पलानीस्वामी ने 234 में से 169 सीटें अपनी पार्टी के लिए रखी हैं। अबुमणि रामदास की पीएमके को 18, जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस को सात और टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम को भी कम सीटें दीं हैं। भाजपा को उसकी पसंद की सीटों ने देकर पलानीस्वामी ने अपना दबदबा कायम रखा है।

पूंजी संभाले कांग्रेस

आ खिर क्या हो गया है देश की सबसे पुरानी पार्टी को, जिसने राजनीतिक दलों की संस्कृति और लोकतंत्र का आगाज किया था। लेख में सही उल्लेख किया गया है कि सत्ताधारी दल भाजपा से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मगर तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी के तेवर और संघर्ष में बहुत कुछ सीखने के लिए है, जो एक-एक आम मतदाता का हिसाब-किताब बखूबी रख रही है। यहां तो विधायकों का कोई पुरसाहाल नहीं है। कांग्रेस के विशाल वैचारिक आधार वाली पार्टी में बिना विचारधारा वाले लोगों को विधानसभा का टिकट ही क्यों दिया जाता है? जो मौके पर कांग्रेसी ठहरते ही नहीं हैं। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब उन्हें गठबंधन सहयोगी दल भी नहीं मिलेंगे। उसके सारे नाज-नखरे धरे रह जाएंगे। कहीं ऐतिहासिक पार्टी इतिहास न बन जाए। हालांकि कांग्रेस की विचारधारा उसे ऐसा नहीं होने देगी। यही उसकी पूंजी है, अपनी पूंजी तो संभाले नेतृत्व।

मिस्त्री की तलाश!

पुरानी गाड़ियों की कतार में खड़ी मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात की तस्वीर है ‘गुड्री कंडम हो रही है’। ‘जोड़ा बैल’ से चल कर ‘पंजा’ तक के सफर में इस जमात का कारवां अजीब-ओ-गरीब रास्ते से गुजरा है। जंजीर की कुछ कड़ियों को छोड़ बदलते श्वल-ओ-सूरत में इस जमात को ‘सबसे पुरानी’ होने का दर्जा देना भी मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल जब पुरानी गाड़ी के कल-पुर्जे ही ढीले हों तो सफर करते मुसाफिर कहीं और कभी भी उतर जाएं, हैरानी नहीं होगी। इंजन में गुरहट पैदा कर इन्हार-ए-सेहत की होती कोशिश हमने कई बार देखी है। मगर टंटे पड़े पुर्जों में हरकत दूर की कौड़ी साबित हुई। इस पुर्जे कहानी का सिरा हालिया राज्यसभा के चुनावी नतीजों से जा मिलता है। लोग कहते हैं कि जीतीं बाजी हारने का हुनर सिर्फ मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात के पास है। सूबों और राज्यसभा के चुनावी नतीजों ने इस हकीकत का बार-बार सबूत दिया है। बहरहाल उस मिस्त्री की तलाश है जो नए-पुराने पुर्जों के सही इस्तेमाल से नया होने का अहसास पैदा कर दे।

कार्यकर्ता कहां हैं?

आज इसान सुख-सुविधाओं के लोभ में अपनी संवेदना, स्वतंत्रता और न्याय की बलि देने के लिए हमेशा तैयार है। लग रहा है कि बुनिया में कहीं ना



आपके पत्र

सिखांत बचा है और ना आदर्श बचे हैं। सिखांत और आदर्श की पोटली बना कुएं में डाल दिया गया है। निगहबानों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। कांग्रेस व महागठबंधन वोट चोरी करते-करते इनके खो गए कि राज्यसभा चुनाव में गठरी ही ले भागा चोर। विपक्ष की संभावना सत्ता पक्ष से अधिक होती है। आज विपक्ष नेता विहीन है। इसके चलते अनुशासनहीनता बढ़ी है। सब के सब नेता हो गए हैं। कार्यकर्ता कोई नहीं। आज सबसे अहम सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष और वाम ताकतें हाशिए पर चली गई हैं। धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्रवाद और वाम को नव उदारवाद ने लील लिया है। नेहरू जी ने कहा था कि एक बहुधर्मीय मुक्त में बहुमत की साम्राज्यिकता अपने आप को राष्ट्रवाद के लबादे में पेश करती है। यह कभी राज्य पर कब्जा जमा सकती है। विपक्ष की मजबूत मिसाल ममता बनर्जी हैं जिन्होंने एसआइआर का मुद्दा उठाया ही नहीं, सड़क से न्यायालय तक खुद पैरोकार बनीं। अपने एक-एक मतदाता की निगहबानी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस एक खटारा गाड़ी बनकर रह गई है। इसके सड़क पर लाने के लिए ‘ओवरहाल’ कराने की जरूरत है।

—रामानुज चोधरी, बेगूसराय।

अतीत का रुतबा

राजनीति में सफलता जमीनी संघर्ष, अनुशासन और चुनाव प्रबंधन से मिलती है। कांग्रेस में जमीनी संघर्ष सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उसे चुनावी सफलता में बदलने वाले अनुशासन और चुनाव प्रबंधन से उन्हीं ने मुंह मोड़ रखा है। कांग्रेस के तमाम तथाकथित कद्दावर नेता भी संघर्ष, अनुशासन और चुनावी प्रबंधन से दूर हैं। वर्तमान में बिना कोई बड़ा योगदान दिए ये नेता अतीत के रुतबे के आधार पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं और चुनौती

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

वाहन खरीदारी में दिखाएं ज्यादा समझदारी

वर्तमान हालात को देखते हुए ऑटोमोटिव कंपनियां अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। वहीं, खरीदारों में महंगाई, ईंधन के भावी दाम को लेकर आशंकाएं हैं। वाहन बाजार के अनुमान बताते हैं कि वाहन बिक्री अपनी गति से जारी रहेगी। अगर आपने वाहन खरीदारी की योजना इस दौरान बनाई है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको कैसे वाहन खरीदने चाहिए? वाहन खरीदने के फैसले को आप किन कसौटियों पर परखेंगे, आइए जानते हैं...

सर्विस नेटवर्क भी एक कसौटी

विश्वसनीय ब्रांड्स का सर्विस नेटवर्क व्यापक होने के कारण स्पेयर पार्ट्स आसानी से और सस्ते मिलते हैं। एक लोकप्रिय ब्रांड भरोसा और बचत, दोनों की राह बनाता है। इस संदर्भ में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई फोर व्हीलर के सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड हैं। वहीं, दोपहिया वर्ग में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा टच पॉइंट्स के लिए जाना जाता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 6500 से अधिक टचपॉइंट्स हैं। होंडा और टीवीएस का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। ताजा हालात में खरीदारी भावनात्मक आधार पर एक उपयोगिता के आधार पर करना ज्यादा फायदेमंद सौदा होगा। शायद यही कारण है कि अब लोग एक वाहन खरीदने से पहले यूट्यूब, रिव्यूज, तुलना आदि के शोध अनिवार्य रूप से अपने स्तर पर कर रहे हैं।



पैसे के नजरिए से सही मायने समझना भी जरूरी है। इन दिनों लोकप्रिय वेंटिंग मॉडल्स पर अक्सर कुछ लाख रुपये तक का प्रीमियम या एक्ससेसरीज का अतिरिक्त बोझ आता है। इसके विपरीत, यदि आप शोरूम में उपलब्ध तैयार वाहन या पिछले साल के मॉडल्स चुनते हैं, तो आप नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट लाभ मिलानकर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की सीधी बचत कर सकते हैं। वैसे भी इस समय वित्त वर्ष की क्लोजिंग के चलते कई लोकप्रिय मॉडल्स पर छूट ऑफर हो रही है, जो अप्रैल में ज्यादा दाम में बदल सकती है।

रीसेल वैल्यू भी देखें

मारुति स्विफ्ट जैसे लोकप्रिय मॉडल 5 साल बाद भी अपनी 60 फीसदी से अधिक वैल्यू बचाए रखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वैगन आर जैसी कारों की रीसेल वैल्यू अच्छी है। वहीं टोयोटा हाइक्रॉस इस मामले में किंग कही जाती है। यानी आज के दौर में गाड़ी खरीदना केवल शोरूम प्राइस का खेल नहीं है। कई ऐसे आधुनिक डिजिटल टूल्स आ गए हैं, जिनके आधार पर आप अपनी कार के पांच साल बाद की वैल्यू के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज बुक वैल्यू (ओबीवी)। यह रीयल-टाइम मार्केट डेटा का उपयोग करते हैं और लंबी अवधि में आपके वाहन की कीमत में गिरावट का स्पष्ट अंदाजा देते हैं।

उम्मीद भरे आंकड़े

सरकार के 'वाहन' पोर्टल पर 1 से 17 मार्च तक के डेटा के अनुसार, कुल वाहन पंजीकरण 12.54 लाख यूनिट्स रहा, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 9.92 लाख यूनिट्स की तुलना में 27% अधिक है। ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में वाहनों की मांग है, खासकर एसयूवी और कम ईंधन खर्च वाली गाड़ियों की मांग मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों से मांग में सुधार और एसयूवी व इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की रिपोर्ट-टोड बिक्री के चलते, ऑटोमोबाइल उद्योग 2022 के बाद से फिलहाल अपने सबसे शानदार प्रदर्शन की राह पर दिखा है।

रूपाली चतुर्वेदी



और मजबूत सेवा नेटवर्क इस समय सबसे व्यावहारिक आधार माने जा रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन किफायती

लंबी दूरी या छोटे शहरों में अभी भी पेट्रोल और मिश्रित ईंधन वाले विकल्प ही अधिक व्यावहारिक माने जा रहे हैं। हालांकि, ईंधन महंगा होने पर शहरों में चलने वाली के लिए इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगी साबित होंगे। बता दें कि इस साल फरवरी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेट कुल बाजार में 5 फीसदी रही है। यदि घर पर चार्जिंग की सुविधा है और रोज सीमित दूरी तय करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन सबसे अच्छा चयन होंगे।

ओनरशिप कॉस्ट समझें

कुल टीओसी यानी मालिकाना खर्च को समझना जरूरी है। इसके लिए नए वाहन के 5 साल का खर्च निकालें। यदि आप एक 12-15 लाख रुपये की पेट्रोल एसयूवी लेते हैं, और 5 साल तक 50,000 किमी चलाते हैं, तो बोमा, मेटेंस, वैल्यू डेप्रिशीयेशन आदि को मिलाकर खर्च लगभग 8.5-10 लाख रुपये के बीच आता है। ध्यान रखें कि एक औसत एसयूवी के लिए वास्तविक परिस्थितियों में 12 किलोमीटर का माइलेज यहां लिया गया है। इसके विपरीत, एक समान बजट वाली इलेक्ट्रिक कार का 5 साल का खर्च 2.5

लाख से 3 लाख बैठता है, क्योंकि इसकी ईंधन पर आने वाला खर्च 1.2 रुपये प्रति किमी के आसपास है और सर्वाधिक में बहुत कम पुर्जे बदलने पड़ते हैं।

जरूरत देख खरीदें, ट्रेंड से नहीं

भारतीय बाजार में इन दिनों एसयूवी का दबदबा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी 2025-26 में बढ़कर लगभग 55 फीसदी तक पहुंच गई है। हालांकि, केवल 'ट्रेंड' के पीछे भागने के बजाय अपनी जरूरत का आकलन करना अधिक समझदारी है। यदि आपका 90 फीसदी उपयोग शहर के भीतर है, तो एक हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान आज भी कहीं अधिक व्यावहारिक विकल्प है। किफायत की

सुरक्षा सुविधाओं से लैस कुशाक

जनवरी 2026 में पहली बार सामने आई नई कुशाक फेसलिफ्ट अब बाजार में पहुंच चुकी है। यह कार भारतीय बाजार में पांच साल बाद फिर आई है और इसमें 25 से अधिक मानक सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं।

नई कार

स्कोडा कुशाक के नए फेसलिफ्ट मॉडल को पांच वैरिएंट में लाया गया है, जिसमें क्लासिक प्लस, स्पिन्चेर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मॉटे कालों शामिल हैं।

इंजन - दो टर्बो पेट्रोल विकल्प दिए जा रहे हैं - 1.0 टीएसआई या 1.5 टीएसआई, जिसमें मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। इसका 1.0 टीएसआई इंजन 114 बीएचपी की पावर और 178 एनएम का टॉक देता है। यह 6-स्पीड मैनुअल या 8-स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसकी एआरएआई ईंधन दक्षता यानी माइलेज की बात करें, तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.66 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 19.09 किमी

प्रति लीटर है।

कुशाक फेसलिफ्ट के 1.5 टीएसआई इंजन संस्करण में 148 बीएचपी की पावर और 250 एनएम का टॉक मिलता है। इसमें 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। एआरएआई के अनुसार, इसकी प्यूल एफिशिएंसी 8.72 किलोमीटर प्रति लीटर है।

सुरक्षा में कैसी - सभी वैरिएंट को ग्लोबल एनकेप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। टॉप वैरिएंट में 40 तक सेफ्टी फीचर्स हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स में 6

एयरबैग, लेवल 2 अडवांस दिया गया है। अन्य फीचर्स में एलईडी हेडलैंप और टेललैंप, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और क्लाइमेट्रॉनिक ऑटो एसी शामिल हैं। हाई ट्रिप्स में वचुअल कॉन्फिग, पैनोरमिक सनरूफ और पिछली सीट पर मसाज भी मिलते हैं।

आठ रंगों में आइ: नई कुशाक 8 रंगों में उपलब्ध है, जिनमें तीन नए शेड्स शामिल ग्रीन, स्टील ग्रे और चेरी रेड शामिल किए गए हैं। फेसलिफ्ट के साथ 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ 4 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 2 साल या 30,000 किलोमीटर तक चार लेबर-फ्री सर्विस मिलती हैं। कीमत एक्स-शोरूम 10.69 लाख रुपये से शुरू।

नरेंद्र



कार बाजार

यदि आप नियमित रूप से गाड़ी चलाते हैं, तो आपने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जरूर सुना होगा। सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर चर्चा करते समय इस शब्द का अक्सर उल्लेख किया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट ड्राइव करते हुए कार के आसपास का वह हिस्सा होता है, जहां चालक वस्तुओं या अन्य वाहनों की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता।

ब्लाइंड स्पॉट की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही कारों के लिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग अब एक प्रीमियम फीचर से बदलकर एक अनिवार्य सुरक्षा जरूरत बन गया है। कुछ कारों में भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह सिस्टम बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। आइए जानें, विभिन्न सेगमेंट की ऐसी कुछ एसयूवी, जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ आती हैं:

महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सओ

महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सओ मौजूदा समय में



भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे उपयोगी ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम में से एक मुहैया करती है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये है। इस कार में एसे स्मार्ट सेंसर और कैमरे लगे हैं, जो सड़क पर नजर रखते हैं। कार में कोलिजन अर्वायडेंस और लेन असिस्ट जैसे फीचर्स भी हैं। अगर अचानक कार के सामने कोई आ जाए और ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए, तो कोलिजन अर्वायडेंस सिस्टम खुद ब्रेक लगाकर टक्कर रखने की कोशिश करता है।

नई रेनो डस्टर

10.29 लाख रुपये एक्स शोरूम की कीमत से शुरू होने वाली नई रेनो डस्टर बीटी 17 मार्च को लॉन्च हो चुकी है। ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीक के साथ इसमें शानदार ग्राउंड क्लियरेंस और रफ-टफ लुफ्ट जैसे कई खास आकर्षण हैं। इसमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं और जल्द ही एक हाइब्रिड मॉडल भी इसमें शामिल होगा। नई डस्टर न केवल चलाने में मजेदार और सुरक्षित है, बल्कि यह लंबी दूरी की यात्राओं के लिए किफायती एसयूवी भी साबित होगी।

वहीं, लेन असिस्ट ड्राइवर को कार को दोबारा सही लेन में लाने की चेतावनी देता है। इस सिस्टम को भारतीय ट्रैफिक की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह टर्बोपेट्रोल और टर्बोडीजल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

टिग्वान आर लाइन

प्रीमियम सेगमेंट की वोक्सवैगन टिग्वान आर लाइन दिखने में बहुत तड़क-भड़क वाली नहीं लगती, लेकिन इसका ब्लाइंड-स्पॉट

आमतौर से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर बाहर के कुछ हिस्सों को देख पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। इन्हें ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसके समाधान के लिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम अब हर कार की जरूरत है। यहां हम दे रहे हैं ऐसी चार कारें, जो बनाएंगी ड्राइविंग को आसान :

टाटा हैरियर

12.89 लाख एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत वाली टाटा हैरियर की सुरक्षा में अडवांस फीचर्स और 360 डिग्री कैमरा जुड़ने से महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। अगर आप हाईवे पर बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो अपने बड़े व शक्तिशाली इंजन और शानदार सर्पेसशन सेटअप के साथ टाटा हैरियर आपके लिए बेहतरीन एसयूवी है। इसकी लोकप्रियता युवाओं में बहुत अधिक है।

मॉनिटरिंग सिस्टम काफी सटीक है। यह रडार-आधारित डिटेक्शन और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट पर निर्भर करता है। 1200 पीएस की ताकत वाला इंजन और 7-स्पीड डीएसजी वाला गियरबॉक्स इस कार को सबसे खास बनाता है। अगर आपको लॉन ड्राइव पर जाना पसंद है, तो यह एसयूवी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इस कार कीमत 45.73 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

Hindustan Times



पं. राघवेंद्र शर्मा ज्योतिषाचार्य

मेघ : आत्म संयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। दूसरों से वाद-विवाद न करें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा।

वृष : मन अर्थात रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकते हैं।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार के विस्तार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आय वृद्धि होगी।

कर्क : मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। आत्म-विश्वास भी भरपूर रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भाग-वैद अधिक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्म विश्वास में कमी रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। भागवैद भी अधिक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। लाभ में वृद्धि होगी।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्म संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला : आत्मविश्वास से लबरज रहेगे। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से भरपूर रहेगे। मन लेकिन परेशान हो सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय में वृद्धि होगी।

धनु : आत्मविश्वास से लबरज रहेंगे। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। परंतु बातचीत में संतुलित रहें। कारोबार में भागवैद अधिक रहेगी। कारोबार के लिए विदेश यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। आत्म संयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में भी बढ़ोतरी होगी।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में बाधा आ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। भागवैद अधिक रहेगी।

रोजनामचा

वर्ग पहली: 8281

	1	2	3	4	5
6			7		
		8			
9	10				
11		12	13		
14		15	16		
17			18		
19			20		

बाएं से दाएं
3. रश्मि; अचल; अटल (4)
6. जिनता का हित चाहने वाला; जनसेवक; लोकसेवा करने वाला; लोकसेवी (5)
8. चटक मटक; दीपित; तड़क भड़क; शान (3,3)
9. अकस्मिक; अचानक; एकाएक (3)
11. डाली; पतली शाखा (3)
12. घातक; नाशक; भयानक; मर्मांतक; हिंख (3)
16. किसी घटना का मंच पर प्रदर्शन; मंचन योग्य कथा (3)
17. चमक दमक; ठसक; नाज नखरा; बनाव सिंगार; वेशविन्यास और हावभाव (3,3)
19. छुट्टी मारना; नियम तोड़ना (2,3)
20. आदमी-ओरत; नर-नारी; (2,2)

ऊपर से नीचे
1. चिकना होने का भाव; चिकनापन (5)
2. छाल; आवरण; जिरह बखर (3)
4. झगड़ा करना; दावा करना; बहस करना; मुकदमा चलाना (3,3)
5. ऊंचे स्थान से बंधना; झूलना; टंगना (4)
7. शरीर का मध्य भाग; कटि (3)
10. जीवट दिखाना; जोखिम भरा काम करने का प्रयास करना; हिम्मत करना (3,3)
13. कट कर मर जाना; जान की बाजी लगा देना; लड़ मरना (2,3)
14. जल पीना; मुखशुद्धि हेतु जल लेना; मंत्र पढ़ कर दाहिने हाथ से जल पीना (4)
15. तल से तल मिलना; चिपकना; (3)
18. नदी का किनारा; ऊंचा टीला (3)

वर्ग पहली: 8280

1. स 6 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 स 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9
6 7 8 9
7 8 9
8 9
9

सुडोकू: 8263

3	5	8			
			3		
7			6		3 1
		6			9 7
4 1				8	
1 2		4			6
	6		5		
				1 7	4

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबर्स की पहली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएँ। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू: 8262

6 5 3	7 8 1	4 2 9
4 9 7	5 6 2	3 1 8
1 8 2	9 4 3	5 7 6
9 2 4	6 1 8	7 3 5
7 3 8	4 5 9	2 6 1
5 1 6	2 3 7	9 8 4
8 4 9	3 2 6	1 5 7
2 7 1	8 9 5	6 4 3
3 6 5	1 7 4	8 9 2

व्रत और त्योहार | पंचांग

28 मार्च, शनिवार, शक संवत्: 07, चैत्र (सौर) 1948, पंचांग पंचांग: 15, चैत्र मास प्रवृत्त 2083 इस्लाम: 08 शवाल 1447, विक्रमी संवत्: चैत्र शुक्ल दशमी तिथि प्रातः 08.46 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, गर करण चन्द्रमा कर्क राशि में (दिन-रात) सूर्य उतरायण। सूर्य उत्तर गोल। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 08.17 बजे से। श्री धर्मराज दशमी। नवरात्र व्रत पारण। गण्डमूल दोपहर 02.51 मिनट से।

वास्तुसलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

ईएमएफ क्या होता है और वास्तु के अनुसार कैसे प्रभावित करता है? -प्रभास, दिल्ली किसी भी भवन में बिजली के उपकरणों या वैद्युर सिंग से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसे ईएमएफ कहते हैं। लगातार इस प्रभाव में रहने के कारण शरीर की कोशिकाओं की कार्यप्रणाली और नौद पर असर पड़ सकता है। जिससे गहरी नौद न आने की समस्या हो सकती है। सुबह उठने पर भारीपन, सिरदर्द हो सकता है। लंबे समय तक संपर्क से एकप्रता कम हो सकती है। ज्यादा संवेदनशील लोगों की त्वचा में झुनझुनी हो सकती है। उपाय के तौर पर नियमित नंगे पैर जमीन या घास पर चलें। सोते समय सिर के पास मोबाइल चार्जर या बिजली के बोर्ड न हों।

Last Day To Join Private channel

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS PURCHASE WILL BE WORTH IT.

Indian Newspapers:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| <u>1) Times of India</u> | <u>6) The Hindu</u> |
| <u>2) Hindustan Times</u> | <u>7) Live Mint</u> |
| <u>3) Business line</u> | <u>8) Financial Express</u> |
| <u>4) The Indian Express</u> | <u>9) Business standard</u> |
| <u>5) Economic Times</u> | <u>+All Editorial PDFs</u> |

International Newspapers Channel

Magazine Channel (National & International)

Uploding starts from
5AM

Access to all this
In Just 19 Rupees
[lifetime Validity]

Click below to

Join



चिंतन

परिस्थितियां कठिन लेकिन भरोसा रखें

वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है, खासकर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और स्पलाई चैन पर। हालांकि, हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन घबरावने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सरकार पर भरोसा रखने का समय है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार और संबंधित मंत्रालयों ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि सभी रिफ़ाइनरी 100 प्रतिशत क्षमता से काम कर रही हैं और स्पलाई चैन को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एलपीजी के उत्पादन में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकार स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाल के दिनों में कुछ अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिससे लोगों में अनावश्यक भय का माहौल बना, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ऐसी अफवाहें ही असली समस्या को बढ़ाती हैं। जब लोग जरूरत से ज्यादा इंधन या गैस खरीदने लगते हैं तो स्पलाई पर दबाव बढ़ता है और अस्थायी संकट पैदा हो सकता है। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना काल के संदर्भ में दी गई टिप्पणी को भी कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य केवल यह बताना था कि उस समय लॉकडाउन एक विशेष परिस्थिति में लगाया गया था, जबकि वर्तमान हालात उससे अलग हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस बात की पुष्टि की है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। कोरोना काल में लोग एक-दूसरे के संपर्क में न आए, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था। अब ऐसे हालात नहीं हैं, इसलिए लॉकडाउन नहीं होगा। परिस्थितियां भले ही कठिन हों, लेकिन लोग धवर्णाएं नहीं, पैनीक न हों, सरकार पर भरोसा रखें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जहां पहले यह लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं अब 110 डॉलर के पार पहुंच चुकी है। इसका सीधा असर तेल कंपनियों पर पड़ा है, जिन्हें प्रति लीटर 30 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा था, लेकिन सरकार ने एक्सट्राज ड्यूटी में कटौती कर जनता को राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये की कटौती से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है। शुरूआत में कर्मशियाल उपयोग के लिए स्पलाई कम की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर लगभग 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है। भारत की कूटनीति भी इस कठिन समय में एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आई है। रूस, अमेरिका, ईरान और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ संवाद स्थापित कर भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित किया है। यह दिखाता है कि देश केवल आंतरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सक्रिय और सक्षम है। इन सभी प्रयासों के बावजूब यह मानना होगा कि परिस्थितियां पूरी तरह आसान नहीं हैं। वैश्विक संकट का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ता ही है, लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण है जनता का धैर्य और सरकार पर विश्वास। परिस्थितियां भले ही कठिन हों, लेकिन विश्वास और संयम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।



मुद्रा

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

दुनिया के विभिन्न देशों में इच्छा-मृत्यु पर अलग-अलग बहस है। कई देशों ने इसे मान्यता भी दी है, लेकिन भारत में इसकी स्वीकृति विशेष परिस्थिति में ही मिलती है। अब जब हरीश राणा के बहाने इच्छा मृत्यु एक बार भारत में जीत गई है तो भारत को पुनः सोचना होगा कि कैसे हम आने वाले समय में ऐसे आवेदकों से निपटेंगे। यह सोचना होगा कि हम किस स्तर पर इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दें। न्यायालय और सामाजिक न्याय के बीच जीवन व गरिमा का यह युद्ध अब नया रूप न ले ले और हम भारत के लोग कहीं लक्षित न होने लगे, इस पर भी विचार करना होगा। यह विचार भी जरूरी है कि मानवाधिकारों की बहस में इच्छा-मृत्यु कहीं सभ्यता पर ही न सवाल करने लगे।

इच्छा मृत्यु की जीत से उपजे सवाल

दिल्ली में 2014 से जीवन व मृत्यु को जंग लड़ रहे हरीश हार गए और इच्छा-मृत्यु जीत गई। इस जीत ने मानवाधिकार को हरा दिया। दुनिया के विभिन्न देशों में इच्छा-मृत्यु पर अलग-अलग बहस है। कई देशों ने इसे मान्यता भी दी है, लेकिन भारत में इसकी स्वीकृति विशेष परिस्थिति में ही मिलती है। गीता के अनुसार, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुव जन्म मृतस्य च। जिसका तात्पर्य है कि जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद नया जन्म ध्रुव सत्य है। इसलिए जन्म और मृत्यु के सौंदर्य को भारतीय मानस उत्सव का स्वरूप प्रदान करता है। भारतीय मानस की कल्पना है कि जीवन आनंदमय है और मृत्यु भी आनंदोत्सव के रूप में वरेण्य है। जैन, बौद्ध, हिन्दू और लगभग सभी धर्मों ने कुछ न कुछ इस प्रकार की चर्चा अपने धर्मशास्त्रों में की। किंतु फिर भी जन्म तो उत्सव के रूप में खूब स्वीकार्य रहा। मृत्यु शोक, जीवन-इच्छा से विरक्ति एवं अवसाद के रूप में ही ज्यादा समझी गई। अपनों के जाने का शोक, अपनों से बिछुड़ने का शोक और फिर कभी न मिल पाने का शोक इतना जल्दी स्वीकार नहीं हो पाता और न ही इसे कोई उत्सव के रूप में मनाता है।



बहुत पहले की बात है, मेरे नाना के पिता 140 वर्ष के हो गए थे। तीन पंशन उन्हें मिलती थी। हर महीने आईबी के लोग यह पता करने आते थे कि यह पंशन कोई और तो नहीं ले रहा है। लेकिन हर महीने वे जिंदा मिल जाते थे तो जांच अधिकारी कुछ भी कहे बगैर चले जाते थे। मेरे नानाजी की मृत्यु भी 115 वर्ष में हुई। उनके पिताजी की मृत्यु हो ही नहीं रही थी तो पण्डितों से पूछा गया कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। शरीर बूढ़ा और कमजोर हो गया था, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही थी। मुझे बताया गया कि पिंडतों ने कहा कि इनकी मृत्यु यहां होगी ही नहीं। यदि इन्हें जिंदा बनारस ले जाया जाए तो काशी में कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो सकती है। कहते हैं कि उन्हें जीते जी उत्सव के साथ गाजा-बाजा के साथ हाथी के जुलूस के साथ जिंदा कफन सहित बड़ी तादात में लोग हजारों लोग काशी के लिए बिदा करके आए और वहां सवा महीने रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई। अखबारों में उनकी मृत्यु के विषय में लिखा गया। लोग कहते हैं कि मृत्यु आए तो इतनी जल्दी से आ जाए। न आए तो वर्षों की प्रतीक्षा। कौमा में पड़े व्यक्ति के जीवन का भी क्या? जिंदा लाश, जी भी रहा है तो उससे परिवार, सगे-संबंधियों को केवल रोज मरना व जीना पड़ता है।

अपनी सुध खोया हुआ, मृत-प्राय मनुष्य को तो कुछ पता भी नहीं होता। मृत्यु के नखरे के साथ जुझते लोग और उनके परिजन और डॉक्टर ऐसी स्थितियों में अनिर्णित स्थितियों में जीने को विवश होते हैं। निर्णय क्षमता की परीक्षा बहुत ही कठोर होती है। ऐसी ही कुछ स्थितियां तेरह वर्ष से अधिक समय से कोमा में पड़े हरीश राणा और उसके परिवार व चिकित्सकों की थी। अब हरीश नहीं हैं। प्रेक्षक यह स्वीकार कर रहे हैं कि परिजन व चिकित्सक को बहुत बड़ी राहत मिली है अब और सबसे अधिक राहत उस दिवंगत आत्मा को मिली होगी जो इतने लंबे समय से एक शरीर में कुछ कैद, कुछ उलझी हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भारतीय

अनेक इच्छा मृत्यु के लिए कोशिशों ने अपनी कानूनी मान्यता प्राप्त कर लीं। यह मान्यताएं भी पूरे विश्व में अपना असर दिखाने लगी हैं। भारी संख्या में विश्व भर में इच्छा-मृत्यु के लिए मिले आवेदन हेरान कर देने वाले हैं। अब दुनिया में अवसाद बढ़ रहे हैं।

भूख और गरीबी भी हैं। शरणार्थियों के अपने घर नहीं हैं और न ही उनकी नागरिकता। ऐसे में वे भी अपने जीवन से तंग आकर यदि इच्छा मृत्यु की मांग करने लगे तो क्या होगा? भारत में जिन बुजुर्गों की सेवा करने वाले नहीं होते। जिन्हें अपने बच्चे किसी आश्रम में छोड़ जाते हैं या अपमानजनक स्थिति में पहुंचा देते हैं, उनके मन व मस्तिष्क में बरबस आता है, ऐसा कि हे भगवान! हमें उठा लो। सोचिए अगर वे अपने जीवन से मुक्ति की मांग आवेदन देकर करने लगे तो क्या होगा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दी है उससे जीवन व मृत्यु से जुझते लोगों व उनके परिजनों को कितनी राहत मिली, पता नहीं लेकिन भारत भी इसके लिए राजी हो ही गया और थोड़ा अलग तरह से राजी हुआ। माना कि यह वैज्ञानिक युग है। साइंटिफिक आविष्कारों ने जीवन को दीर्घजीवी बना दिया है। कृत्रिम ढंग से जीने की भी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारा जीवन गरिमामय हो, अर्थपूर्ण हो। मृत्यु भी गरिमामय मनुष्य चाहता है लेकिन मृत्यु का पैमाना कहीं अनेक जीवन को खो देने से न निर्धारित होने लगे, इसके लिए इच्छा मृत्यु पर खुली छूट भी तो नहीं दी जा सकती। हम जीवन से खेलने के आदी न हो जाएं, इसके लिए भी यह छूट नहीं दी जा सकती।

जैन धर्म में भी कुछ प्रथाओं पर इस वजह से प्रश्न खड़ा किया जाता रहा है। दूसरे धर्मों में भी ऐसी चीजें जो अपना आकार ले रही थीं, उन पर समय-समय पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। अब जब हरीश राणा के बहाने इच्छा मृत्यु एक बार भारत में जीत गई है तो भारत को पुनः सोचना होगा कि कैसे हम आने वाले समय में ऐसे आवेदकों से निपटेंगे। यह सोचना होगा कि हम किस स्तर पर इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दें। न्यायालय और सामाजिक न्याय के बीच जीवन व गरिमा का यह युद्ध अब नया रूप न ले ले और हम भारत के लोग कहीं लक्षित न होने लगे, इस पर भी विचार करना होगा। यह विचार भी जरूरी है कि मानवाधिकारों की बहस में इच्छा-मृत्यु कहीं सभ्यता पर ही न सवाल करने लगे।

(लेखक जीतूचंद्र बट्टिसिंह ने चैर प्रोफेसर हैं वे उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

संसाधन

बलकार सिंह पूनिया



ऊर्जा संकट और गांवों की ओर लौटता समाधान

वर्तमान ऊर्जा संकट केवल ईंधन की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास मॉडल की बुनियादी कमजोरियों को उजागर करता है। लंबे समय से अपनाया गया शहर-केंद्रित विकास ढांचा सुविधाओं और उपभोग पर आधारित रहा है, जिसने जीवन को आधुनिक तो बनाया, परंतु उसे बाहरी संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर भी कर दिया। परिणामस्वरूप, गैस, बिजली या अन्य ऊर्जा स्रोतों में थोड़ी-सी बाधा भी शहरी जीवन को असंतुलित कर देती है। रसोई से लेकर परिवहन और दैनिक आवश्यकताओं तक सबकुछ प्रभावित हो जाता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि आधुनिक शहरी व्यवस्था जितनी आकर्षक है, उतनी ही संवेदनशील और अस्थिर भी है। इसके विपरीत, भारतीय गांवों की जीवन-शैली आज भी आत्मनिर्भरता, स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। गांवों में व्यक्ति केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार होता है। यही कारण है कि संकट के समय गांव अधिक लचीले और टिकाऊ साबित होते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर हुआ पलायन इस सत्य का प्रमाण है कि जब शहरों की सीमाएं सामने आती हैं, तब गांव ही सुरक्षा और स्थिरता का आधार बनते हैं।

ऊर्जा के संदर्भ में यदि देखा जाए तो गांवों के पास अनेक ऐसे विकल्प हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बायोगैस इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से तैयार की जाने वाली यह ऊर्जा न केवल स्वच्छ और सस्ती है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से गांव अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा कर सकते हैं, जिससे एलपीजी जैसी बाहरी निर्भरता में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया से प्राप्त जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करती है। इस प्रकार बायोगैस केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि एक समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संभावना प्रस्तुत करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति सौर ऊर्जा के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि गांवों में सोलर पैनल, सोलर पंप और माइक्रो-ग्रिड जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए तो न केवल ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि एक विकेंद्रीकृत और टिकाऊ ऊर्जा तंत्र भी विकसित हो सकेगा। यह मॉडल न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। फिर भी, समस्या केवल तकनीकी समाधान की नहीं है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण की भी है। अब तक की विकास नीतियों में गांवों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली, जिसके कारण स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को उपेक्षा हुई है।

आवश्यकता इस बात की है कि विकास की दिशा को पुनः परिभाषित किया जाए और गांवों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास के केंद्र के रूप में स्वीकार किया जाए। इसके लिए पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना होगा, ताकि वे ऊर्जा उत्पादन और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकें। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की भूमिका इस परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। वे घरेलू संसाधनों के प्रबंधन की धुरी होती हैं और यदि उन्हें बायोगैस, सौर ऊर्जा और अन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे न केवल परिवार की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, बल्कि 'ऊर्जा उद्यमों' के रूप में उभरकर अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकती हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। अंततः यह स्पष्ट है कि ऊर्जा संकट का समाधान केवल आयात बढ़ाने या सब्सिडी देने में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाने में निहित है। इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, विकेंद्रीकृत ऊर्जा मॉडल को अपनाया जाए और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए।

आज समय की मांग है कि 'गांवों की ओर लौटने' की अवधारणा को केवल भावनात्मक अपील न समझा जाए, बल्कि इसे एक व्यावहारिक और दूरदर्शी रणनीति के रूप में अपनाया जाए। क्योंकि एक आत्मनिर्भर, संतुलित और संकट-प्रतिरोधी भारत का निर्माण तभी संभव है, जब गांवों की शक्ति, उनकी आत्मनिर्भरता और उनके संसाधन-आधारित जीवन मॉडल को विकास की मुख्यधारा में स्थान दिया जाए।

(लेखक इन्तू लाल दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

आनंदमय कोष की प्राप्ति

आनंदमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष के पश्चात प्रवेश होता है आनंदमय कोष में। अन्न से उत्पन्न यह शरीर त्वचा, मांस, चर्म और रक्षिण युक्त है। यह आत्मा नहीं है। प्राणमय कोष भी आत्मा नहीं, क्योंकि प्राण वायु के रूप में शरीर में आता-जाता है। मनोमय कोष व्यक्ति को विषयों में आसक्त करता है और आत्मभाव में स्थित नहीं होने देता है, इसलिए यह भी आत्मा नहीं है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सुख-दुःख, जन्म-मरण, लाभ-हानि विज्ञानमय कोष में रहते हैं, इसलिए यह भी आत्मरूप आनंदमय कोष नहीं हो सकता है। श्रीरामचरितमानस में मात्र श्रीभरत इन कोषों का उत्पादन रूप में उपयोग करते हुए भी आनंदमय कोष नहीं, जिनका राम से सर्वथा ऐक्य है। सारा संसार भरत को इस महत् भूमिका के कारण ही दीपावली का प्रकाश पर्व मनाता है। दीपावली सनातन संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरा कार्तिक माह घरों तथा व्यापारिक संस्थानों की स्वच्छता व सजावट में लग जाता है। दीपावली के इस दृष्ट बाह्य और लौकिक रूप में कौन-सा आंतरिक तत्व छिपा है, जिसे जानने के पश्चात दीपावली हमें हमारे मूल वैदिक परंपराओं की नींव से जोड़ देती है। श्रीरामचरितमानस में भक्ति के सोपानों का वर्णन अरण्यकांड में है, जिसका विश्लेषण भगवान श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण की जिज्ञासा-समाधान में करते हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के सोपानों का वर्णन मानस के अंतिम उत्तरकांड में काकभुशुंडि जी गरुड़ जी के समक्ष करते हैं।



संकलित दर्शन



संकलित प्रेरणा

अंतर्मन

सद्गुणयोग

हैं...बोले...अब कुछ ऊर्जा मिली...?

ऊर्जा संकट

राजनीति

अजित पाटील

आज की पाती

बातचीत से मुलझाया जाए अमेरिका-ईरान युद्ध

अविश्वस्त भविष्य वाला युद्ध केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं होता, बल्कि यह राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मानवता, सभी को गहराई से प्रभावित करता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का द्विपक्षीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक नृ-राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक तंत्र की विफलता का एक ज्वलंत उदाहरण बन चुका है। युद्धविराम के प्रस्ताव पर जिस तरह दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के प्रति अविश्वास दिखाया, उससे स्पष्ट है कि संवाद की बुनियाद ही कमजोर है। अमेरिका द्वारा प्रस्तुत 15 सूत्रीय प्रस्ताव को ईरान ने खारिज करते हुए अपनी शर्तें सामने रख दीं, जो यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच कोई प्रभावी बैक-चैनल वार्ता नहीं चल रही है। पूरे विश्व के हित में यही है कि इस मसले को बातचीत के जरिये सुलझाया जाए।

- राजेंद्र ठाकुर, रायपुर

करंट अफेयर

अमेरिकी डॉलर पर जल्द दिखाई देंगे ट्रंप के हस्ताक्षर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर जल्द ही अमेरिकी मुद्रा (डॉलर) पर दिखाई देंगे और यह 1861 में डॉलर की शुरुआत के बाद से पहली बार होगा जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मुद्रा पर अंकित किए जाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय ऐसे वक्त लिया है जब अमेरिका इस वर्ष देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अधिकारी ब्रैडन बीच ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा 'अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के हस्ताक्षर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर के साथ जल्द ही अमेरिकी मुद्रा पर दिखाई देंगे। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा और यह राष्ट्रपति के नेतृत्व एवं हमारे महान राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। इस महीने की शुरुआत में, एक संघीय कला आयोग ने अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर ट्रंप की छवि वाले 24 कैरेंट सोने के स्मारक सिक्के के अंतिम डिजाइन को मंजूरी दी थी। बेसेंट ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, हम अभूतपूर्व आर्थिक विकास, डॉलर के स्थायी प्रभुत्व और राजकोषीय मजबूती एवं स्थिरता की राह पर हैं।'



ऑफ बीट

कसरत की थकान से उबरने में आइस बाथ है लोकप्रिय

पिछले कुछ साल में 'आइस बाथ' का चलन तेजी से बढ़ा है। दुनिया भर में खुद को स्वस्थ रखने वाले और व्यायाम करने वाले लोग इसे अपना रहे हैं, हालांकि पहले केवल एथलीट ही इसका उपयोग करते थे। 'आइस बाथ' का मतलब बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़ों से भरे पानी में नहाना है। कसरत की थकान से उबरने के लिए 'आइस बाथ' 'आइस बाथ' लेने का मुख्य कारण मांसपेशियों में दर्द को कम करना और व्यायाम के बाद थकान से उबरना है। धाक, भारोत्तोलक और फुटबॉल खिलाड़ी सहित एथलीट अमतौर पर 'आइस बाथ' का उपयोग करते हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 'आइस बाथ' लेने से कसरत के बाद होने वाली थकान को दूर किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि गहन व्यायाम के तुरंत बाद 'आइस बाथ' लेने से अगले कुछ घंटे और दिनों में मांसपेशियों का दर्द कम हो सकता है। 'आइस बाथ' से मांसपेशियों की ताकत, मजबूती और लचीलेपन जैसी चीजों में मदद मिल सकती है। 'आइस बाथ' से व्यायाम के बाद होने वाली सूजन, मांसपेशियों की सूजन और मांसपेशियों की क्षति जैसी चीजों में सुधार हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगातार कई दिन तक तीव्र व्यायाम करना पड़ता है तो आपके लिए 'आइस बाथ' एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एथलीट है तब भी हमेशा 'आइस बाथ' नहीं लेना चाहिए।



टैंड

नौएडा हवाई अड्डा

28 मार्च अरु प्रदेश और एनडीआर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। नौएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन होगा। इसके व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नौएडा हवाई अड्डा हमारे देश की प्रमुख हरित परियोजनाओं में से एक है।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

कांग्रेस की भावना

कांग्रेस की जिस प्रकार की नकारात्मक भावना है, संसद उसका संरक्षण नहीं है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्टचर के साथ चर्चा करना पसंद नहीं है, हो-हल्ला करना और हड़ताल नवाना ही उसकी परंपरा रही है।

- धर्मोद प्रधा, केंद्रीय शिक्षामंत्री

सरकार की नाकामी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 4 घंटे की प्रोपोज्ड पिक्चर देखने कोजने से अस्वस्थ था कि उन्हें पेटोल पापो पर नेजरो। नाकाम गणना सफकार ने बेवारे सिपाहियों को जनता के गुस्से का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया है।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

आमजन को राहत

वैश्विक स्तर पर पेटोल-डीजल की कीमतों ने लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अधिकतर देशों में आम जनता पर बोझ बढ़ा है। ऐसे समय में भारत उन सुनिश्चित देशों में शामिल हो जहां सरकार ने करोड़ों में कटौती कर आम लोगों को राहत देने का कार्य किया है।

-अश्वतथ ठाकुर, सांसद, भाजपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फेसबुक : 0771-4242221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।